अध्याय III

वाणिज्यिक बैंकिंग में गतिविधियां

3.1 वर्ष 2003-04 के दौरान मजबूत व्यापक आर्थिक परिवेश तथा समर्थनकारी मौद्रिक और वित्तीय नीतियों का वाणिज्यिक बैंकों की कारोबारी वृद्धि तथा वित्तीय-निष्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। देयता पक्ष में जमाराशियों में भारी वृद्धि के साथ-साथ आस्तियों के पक्ष में ऋणों और अग्रिमों तथा निवेशों की भारी वृद्धि के कारण बैंकों के तुलन-पत्रों में और मजबूती आयी। कृषि, लघु उद्योग सहित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में तथा आवास सहित विभिन्न अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों तथा गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों, विशेषकर, खुदरा क्षेत्र को बैंक-ऋण में भारी वृद्धि ने यह दर्शाया कि ऋण तक पहुँच में सुधार हुआ है। ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिमों की निगरानी करने के लिए समन्वित जोखिम प्रबन्ध प्रणालियों, वसूली प्रबन्ध तथा बेहतर कम्पनी संचालन संबंधी प्रथाओं पर निरन्तर ध्यान केन्द्रित करते हुए वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता और लाभ-प्रदता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। सभी तरह के विभिन्न बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) ने और सुधार दर्शाया। इसमें उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि मार्च 2004 से 90 दिन के विवेकसम्मत मानदण्ड को अपनाने के बावजूद, सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में समग्रराशि की दृष्टि से लगातार दूसरे वर्ष भी गिरावट आयी। निम्नतर ब्याज दर द्वारा शुरू की गयी मंद आय वृद्धि के बावजूद हाल के वर्षों में दर्ज की गयी लाभ की उच्च वृद्धि की गति 2003-04 में भी बनी रही जो कि मुख्यतः ब्याजेतर आय में काफी वृद्धि तथा समग्र व्यय को मुख्यतः ब्याज व्यय को काफी मात्रा में सीमित रखने से प्रेरित रही (सारणी III.1)।

2. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियां और देयताएं[1]

3.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्र के आकार ने 2003-04 के दौरान जबरदस्त वृद्धि दर्ज की। कुल आस्तियों की वृद्धि दर 2002-03 की वृद्धि दर के और ऊपर लगभग 6 प्रतिशत बिन्दु उच्चतर 16.2 प्रतिशत थी। सकल देशी उत्पाद के प्रति अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियों का अनुपात उपादान लागत पर चालू मूल्यों पर बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि दर्शाता है। इस प्रकार यह वित्तीय क्षेत्र के और भी गहन होने को इंगित करता है। देयताओं की ओर जमा राशियां बैंकों की कुल देयताओं की लगभग 4/5 भाग बनी रहीं। आस्तियों की ओर देखें तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों में इनके दो प्रमुख घटकों अर्थात ऋण और अग्रिम तथा निवेश के अंश कमोबेश पिछले वर्ष के स्तरों पर ही बने रहे (सारणी III.2)। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों में निवेशों का अंश, हालांकि मामूली-सा गिरा है, वहीं सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का अंश बढ़ा है। अन्य अनुमोदित तथा गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के अंश में गिरावट देखी गयी जो

सारणी III.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आय-व्यय की स्थिति में परिवर्तन

(राशि करोड़ रुपये में)

संकेतक	2002-03		2003-04	
	समग्र राशि	प्रतिशत	समग्र राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आय (क+ख)	**21,313**	**14.1**	**11,422**	**6.6**
क) ब्याज आय	13,785	10.9	3,286	2.3
ख) अन्य आय	7,528	31.3	8,136	25.7
2. व्यय (क + ख + ग)	**15,812**	**11.3**	**6,229**	**4.0**
क) ब्याज व्यय	6,080	6.9	-6,029	-6.4
ख) परिचालन व्यय	4,388	13.0	5,463	14.4
ग) प्रावधान और आकस्मिकताएं	5,344	29.3	6,795	28.8
3. परिचालन लाभ	**10,845**	**36.3**	**11,989**	**29.5**
4. निवल लाभ	**5,501**	**47.5**	**5,194**	**30.4**

[1] अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की देयताओं और आस्तियों का विश्लेषण मुख्य तौर से मार्च के अंत के लेखा परीक्षित वार्षिक खाते के आधार पर किया गया है। 2003-04 के दौरान एक प्राईवेट बैंक अर्थात डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक ने अपनी हैसियत में परिवर्तन देखा जो निजी क्षेत्र के पुराने बैंक की हैसियत से बदलकर निजी क्षेत्र का नया बैंक बन गया। इसका निजी क्षेत्र के नये बैंकों तथा निजी क्षेत्र के पुराने बैंक समूह के तुलन-पत्र तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन पर कुछ सांख्यिकीगत प्रभाव होते हैं।

गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपातों से संबंधित निवेशों पर कठोर मानदण्डों को लागू करना दर्शाती है। तुलन-पत्र में निवेश 2003-04 के दौरान 15.6 प्रतिशत की दर से बढ़े, जिसकी तुलना यदि वर्ष 2002-03 की रिकार्ड वृद्धि से की जाए तो यह 2.5 प्रतिशत की निम्नतर दर से वृद्धि दर्शाती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्र में ऋणों और अग्रिमों के अंश में मामूली-सी वृद्धि हुई, इनके साथ ही मीयादी ऋणों के अंश में भी मामूली-सी वृद्धि हुई।

बैंक समूह-वार स्थिति

3.3 2003-04 के दौरान बैंक समूहों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्र का प्रमुख घटक बना रहा, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जमाराशियों, अग्रिमों और निवेश में बाजार अंश कुछ सीमा तक सीमित ही रहा। जबकि निजी बैंकों और विदेशी बैंकों का अंश वर्ष के दौरान बढ़ा (सारणी III.3)। बैंक समूह-वार समेकित तुलन-पत्र परिशिष्ट सारणी III.1(क) से III.1(ग) में दिया गया है। सभी बैंक समूहों ने दो अंकीय आस्ति-वृद्धि देखी (सारणी III.4)।

वर्ष के दौरान घटबढ़ [2]

3.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रमुख बैंकिंग समुच्चयों की प्रवृत्तियां 2003-04 में जमाराशियों में सुदृढ़ वृद्धि ऋणों में विशेषकर, खाद्येतर ऋण में वृद्धि के कारण, भारी वृद्धि तथा निवेशों में निरन्तर वृद्धि को दर्शाती हैं (सारणी III.5)।

सारणी III.2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समेकित तुलनपत्र

(मार्च की समाप्ति पर) (राशि करोड़ रुपये में)

मद	2003		2004	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
कुल देयताएं	**16,99,197**	**100.0**	**19,75,020**	**100.0**
1. पूंजी	21,594	1.3	22,348	1.1
2. प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	76,288	4.5	94,240	4.8
3. जमाराशियां	13,55,654	79.8	15,75,143	79.8
3.1 मांग जमाराशि	1,64,366	9.7	2,03,142	10.3
3.2 बचत बैंक जमाराशि	3,02,303	17.8	3,73,677	18.9
3.3 मीयादी जमाराशि	8,88,984	52.3	9,98,324	50.5
4. उधार राशियां	87,469	5.1	96,490	4.9
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	1,58,192	9.3	1,86,798	9.5
कुल आस्तियां	**16,99,197**	**100.0**	**19,75,020**	**100.0**
1. भारिबैंक के पास नकद और शेष राशि	86,123	5.1	1,13,246	5.7
2. बैंकों के पास शेष राशि और मांग और अल्पावधि सूचना पर जमाराशियां	75,113	4.4	82,223	4.2
3. निवेश	6,93,753	40.8	8,02,066	40.6
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (क+ख)	5,36,214	31.6	6,39,144	32.4
क) भारत में	5,32,976	31.4	6,36,267	32.2
ख) विदेश में	3,238	0.2	2,877	0.1
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	19,281	1.1	18,100	0.9
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1,38,258	8.1	1,44,822	7.3
4. ऋण और अग्रिम	7,39,553	43.5	8,64,143	43.8
4.1 खरीदे और भुनाये गये बिल	58,813	3.5	67,231	3.4
4.2 नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट *आदि*	3,54,768	20.9	3,71,836	18.8
4.3 मीयादी ऋण	3,25,972	19.2	4,25,076	21.5
5. अचल आस्तियां	20,278	1.2	21,403	1.1
6. अन्य आस्तियां	84,378	5.0	91,940	4.7

टिप्पणी : 2003-04 के बैंकों के तुलनपत्र में रिपोर्ट किए गए अनुसार 2002-03 के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आंकड़े है तथा इसलिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2002-03 में रिपोर्ट किए गए इन आंकड़े मेल नहीं खाएंगे जिन्हें कुछ बैंकों द्वारा 2002-03 के आंकड़ों में सुधार किया गया है।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र

[2] यह उपधारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत सांविधिक विवरणियों पर आधारित है।

सारणी III.3: तुलनपत्र का प्रमुख घटक-बैंक समूह का हिस्सा

(मार्च की समाप्ति पर) (प्रतिशत)

बैंक समूह	अस्तियाँ		जमाराशि		अग्रिम		निवेश	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	75.6	74.5	79.6	77.9	74.2	73.2	78.6	78.0
राष्ट्रीयकृत बैंक	46.5	46.7	50.8	50.4	48.6	47.7	46.5	47.1
स्टेट बैंक समूह	29.1	27.8	28.8	27.5	25.6	25.5	32.2	30.9
निजी क्षेत्र के बैंक	17.5	18.6	15.3	17.0	18.8	19.8	15.5	16.8
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	6.2	6.1	6.7	6.7	6.7	6.5	5.8	5.9
निजी क्षेत्र के नए बैंक	11.3	12.5	8.5	10.4	12.1	13.3	9.7	10.9
विदेशी बैंक	6.9	6.9	5.1	5.1	7.1	7.0	5.9	5.2

जमाराशियां

3.5 बैंकिंग क्षेत्र की सकल जमाराशियों में 2003-04 में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि 2002-03 में दर्ज की गयी 13.4 प्रतिशत (विलयन के प्रभाव के लिए समायोजित) की वृद्धि दर से उच्चतर थी (परिशिष्ट सारणी III.2)। कारोबारी शेष राशियों के लिए ज्यादा आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई उछाल भरी आर्थिक स्थिति, वर्ष के उत्तरार्ध में खाद्येतर ऋण में वृद्धि तथा वित्तीय बाजारों में विभिन्न अन्य गतिविधियों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, पारस्परिक-निधियों के घटक से संबंधित गतिविधियों तथा पूंजी बाजार में बढ़ी हुई गतिविधियों, जिनमें विनिवेशों तथाा विदेशी संस्थागत निवेश निधियों में बढ़ी हुई गतिविधियां भी शामिल हैं, ने वर्ष 2003-04 के दौरान मांग जमाराशियों में उच्च वृद्धि ला दी है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां वर्ष के दौरान 32.1 प्रतिशत की दर से उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं, जबकि 2002-03 में ये 11.3 प्रतिशत की दर से ही बढ़ी थीं, जहाँ मीयादी जमाराशियां 2003-04 के दौरान 15.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि 2002-03 में उन्होंने (विलयन के प्रभाव को समायोजित करते हुए) 13.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शायी (चार्ट III.1)।

सारणी III.4: तुलनपत्र में वृद्धि : बैंक समूह-वार

(मार्च की समाप्ति पर) (प्रतिशत)

मद	2003			2004		
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी बैंक	विदेशी बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4	5	6	7
1. पूंजी	0.6	-6.6	25.8	3.8	3.7	3.3
2. प्रारक्षित और अधिशेष	21.7	21.6	28.4	29.1	22.0	14.5
3. जमाराशियां	12.4	11.4	2.1	15.4	29.6	15.1
3.1 मांग जमाराशियां	7.6	6.6	7.1	11.0	72.4	50.8
3.2 बचत बैंक जमाराशियां	18.3	17.1	22.2	19.6	53.3	40.1
3.3 मीयादी जमाराशियां	11.5	10.3	-2.4	14.4	19.4	-1.1
4. उधार	-14.4	15.8	-12.8	28.5	-4.2	10.8
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	9.4	7.2	24.5	26.7	23.9	47.9
कुल देयताएं / आस्तियां	**11.2**	**11.0**	**2.7**	**16.6**	**23.6**	**16.8**
1. भारिबैंक के पास नकदी और शेष राशि	-8.7	45.0	12.6	26.1	32.5	59.7
2. बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्पावधि सूचना पर मुद्रा	-28.1	-52.7	-59.7	32.1	37.0	52.2
3. निवेश	20.1	9.9	16.2	17.3	25.6	1.9
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	25.4	16.5	27.6	21.2	31.5	6.1
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-11.2	-14.7	-8.8	-4.7	-17.7	11.0
3.3 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियों में	6.6	-1.5	-8.9	6.6	13.8	-11.1
4. ऋण और अग्रिम	14.4	18.9	7.6	14.8	23.0	16.0
जिसमें से : मीयादी ऋण	22.8	26.1	6.0	31.9	26.0	25.3
5. नियत आस्तियां	1.5	1.3	-2.9	6.7	5.7	-10.8
6. अन्य आस्तियां	-3.6	44.4	34.0	8.5	5.6	44.5

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र

सारणी III.5: चुनिंदा बैंकिंग संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

संकेतक	19 मार्च 2004 के अनुसार बकाया	वित्त वर्ष प्रवाह (प्रतिशत)	
		2002-03	2003-04
1	2	3	4
1. समग्र जमाराशियां (क+ख)	15,04,416	16.1 (13.4)	17.5
क) मांग जमाराशियां	2,25,022	11.3	32.1
ख) मीयादी जमाराशियां	12,79,394	16.9 (13.7)	15.2
2. बैंक ऋण (क+ख)	8,40,785	23.7 (16.1)	15.3
क) खाद्य ऋण	35,961	-8.3	-27.3
ख) खाद्येतर ऋण	8,04,824	26.9 (18.6)	18.4
3. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	6,54,758	27.3	25.1

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ों में 3 मई 2002 से विलयन के प्रभाव शामिल नहीं है।
स्रोत : धारा 42(2) के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों की विवरणियां

3.6 सभी बैंक समूहों में, 2003-04 के दौरान जमाराशियों का विस्तार 29.6 प्रतिशत पर सबसे ज्यादा निजी क्षेत्र के बैंकों में था, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 15.4 प्रतिशत तथा विदेशी बैंकों में 15.1 प्रतिशत रहा। मांग और बचत जमाराशियों में विस्तार की दर निजी बैंकों में सर्वोच्च थी, उसके बाद विदेशी बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्थान आता है। मीयादी जमाराशियों के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों ने सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्थान आता है। तथापि विदेशी बैंकों के लिए मीयादी जमाराशियों की वृद्धि दर में गिरावट परिपक्व हो रही जमाराशियों की अदायगी के कारण आयी हो।

बैंक ऋण

3.7 निम्न सरकारी खरीद और उच्चतर उठाव (निकास) के कारण खाद्य ऋण में संकुचन, व्यापक आर्थिक परिवेश में सुधार के कारण खाद्येतर ऋण में निरन्तर वृद्धि तथा रुपया ऋणों की तुलना में उधारकर्ता के लिए तुलनात्मक रूप से निधियों की निम्नतर लागत को दर्शाते हुए विदेशी मुद्रा ऋण की मांग में वृद्धि के चलते 2003-04 के दौरान बैंक ऋण में भारी वृद्धि देखी गयी। वर्ष के दौरान खाद्येतर ऋण की मांग में प्रारम्भिक मंदी की प्रवृत्ति अगस्त 2003 के मध्य से आयी तेजी के कारण पलट गयी जिसे मुख्यतः प्राथमिकता प्राप्त ऋणों, आवास ऋण, खुदरा और औद्योगिक ऋणों में वृद्धि से समर्थन मिला। सकल बैंक ऋण में वर्ष के दौरान 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2002-03 में इसमें (विलयन प्रभाव को घटाकर) 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। बैंक ऋण की इस वृद्धि को खाद्येतर ऋण में निरन्तर वृद्धि से समर्थन मिला जो वर्ष के दौरान 18.4 प्रतिशत बढ़ा जो लगभग 2002-03 की 18.6 प्रतिशत (विलयन प्रभाव को समायोजित करके) की वृद्धि दर के बराबर ही थी।

3.8 2003-04 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्रों ने यह दर्शाया कि बकाया ऋण और अग्रिमों में वृद्धि का प्रमुख अंश अर्थात 79 प्रतिशत मीयादी ऋणों का था। आस्ति-देयता प्रबन्ध में

चार्ट III.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि के घटक

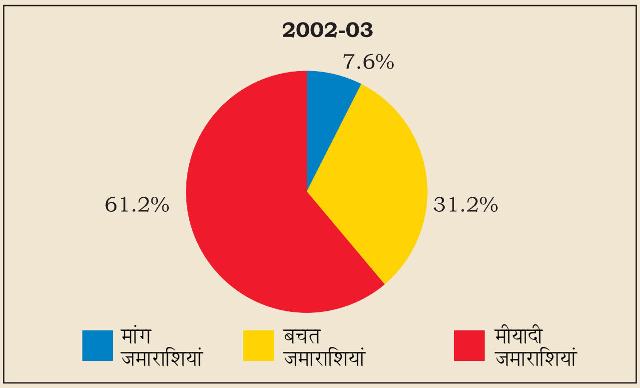

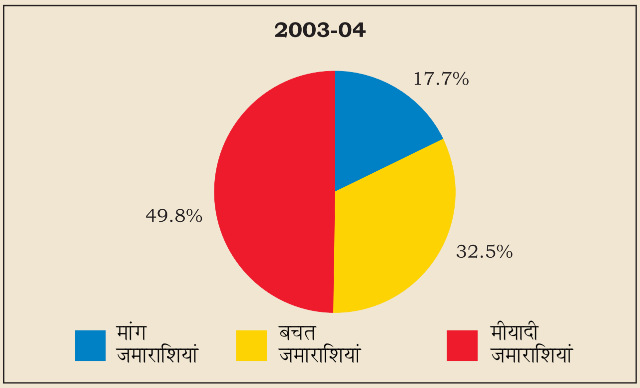

इस सुधार का प्रमाण मीयादी ऋणों में विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। इस विस्तार में मीयादी जमाराशियों का हिस्सा 90 प्रतिशत तक था । बैंक समूहवार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बैंक आस्तियों के ऋणों और अग्रिमों के घटक में विस्तार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लगभग स्थिर गति से तथा निजी और विदेशी बैंकों के लिए तेज वृद्धि दर्शायी। मीयादी ऋणों की वृद्धि सभी बैंक समूहों के लिए उच्च थी। जो आस्ति-देयता प्रबन्ध में सुधार को दर्शाती है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंको ने अपनी मीयादी जमाराशियों के अनुरूप मीयादी ऋणों का विस्तार दर्शाया । तथापि विदेशी बैंकों के लिये मीयादी ऋणों का विस्तार मांग और बचत जमाराशियों में विस्तार करके पूरा किया गया ।

सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय विनियोजन

3.9 भारत सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को ऋण देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बजट 2004-05 में भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि तीन वर्षों में कृषि को ऋण का प्रवाह दो गुना किया जाना चाहिए। तदनुसार, सभी बैंकों से कहा गया है कि वे कृषि ऋण बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय करें। 2003-04 में ऋण का क्षेत्रीय विनियोजन कुछेक सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ा था। गैर-खाद्य ऋण की वृद्धि मुख्यतः प्राथमिकता क्षेत्र, आवासीय और बुनियादी सुविधा क्षेत्रों को दिए गए ऋण के कारण हुई थी (सारणी III.6 और परिशिष्ट सारणी III.3)।

3.10 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (जिनका सकल बैंक ऋण में अंश लगभग 90 प्रतिशत है) द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में 24.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2002-03 में दर्ज वृद्धि दर (विलयन परिणाम के लिए समायोजित) से लगभग 8 प्रतिशत अंक अधिक था। वृद्धिशील आधार पर इस वर्ष प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण का प्रवाह निवल बैंक ऋण में अंतर का लगभग 55 प्रतिशत था, जो 2002-03 की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अंक अधिक था। 2003-04 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण में वृद्धि कृषि क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार में वृद्धि के कारण हुई। 2003-04 में कृषि को ऋण के प्रवाह में 23 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई, जबकि 2002-03 में यह वृद्धि 18 प्रतिशत की थी। लघु उद्योग को प्रदत्त बैंक ऋण में भी 2002-03 में हुई 6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2003-04 में 9 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार में वृद्धि प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास को प्रत्यक्ष ऋण के आधीन रेहन समर्थित प्रतिभूतियों (एसबीएस) में बैंकों के निवेश को सम्मिलित करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण की उच्चतम सीमा बढ़ाने के कारण हुआ है। प्राचीन साक्ष्यों से छोटे परिवहन परिचालकों को ऋण व्यवस्था में वृद्धि का संकेत मिलता है।

3.11 2002-03 की तुलना में 2003-04 के दौरान मध्यम और बड़े उद्योगों को ऋण के प्रवाह में निम्नतर वृद्धि दर्ज की गयी। औद्योगिक ऋण में बड़ी कंपनियों के आंतरिक स्रोतों तथा बाह्य वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों पर बृहतर निर्भरता के कारण कमी आयी। तथापि, बुनियादी सुविधा क्षेत्र को ऋण में 2002-03 के 35.3 प्रतिशत के ऊपर 41.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान थोक व्यापार को बैंक ऋण में काफी वृद्धि हुई। 2003-04 में गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों को बैंक ऋण में कमी देखी गयी। खुदरा ऋण सहित विभिन्न अन्य क्षेत्र को ऋण के प्रवाह

सारणी III.6: सकल बैंक ऋण के क्षेत्रीय नियोजन :प्रवाह

(वर्ष की तुलना में घटबढ़)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2002-03@		2003-04	
	वास्तविक	प्रतिशत	वास्तविक	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	28,540	16.3	52,225	24.7
2. उद्योग (मझौले तथा बड़े)	28,011	16.3	12,042	5.1
जिसमें से: बुनियादी	5,224	35.3	10,927	41.6
3. आवास	12,308	55.1	15,394	42.1
4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4,399	45.6	2,675	18.9
5. थोक व्यापार (खाद्यान्न की सरकारी खरीद से इतर)	1,939	9.5	2,289	10.1
6. अन्य क्षेत्र	9,481	11.5	23,742	23.7
जोड़ (1 से 6)	**84,678**	**17.5**	**1,08,367**	**17.5**
जिसमें से : निर्यात ऋण	6,424	14.9	8,485	17.2

@ आइसीआइसीआइ बैंक में आइसीआइसीआइ के विलय के प्रभाव को छोड़कर।
टिप्पणी :आंकडे अनंतिम हैं और चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हैं जो समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण का 85-90 प्रतिशत बैठता है।

में 2003-04 में 23.7 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि देखी गयीं जबकि 2002-03 में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार, आवास और वैयक्तिक ऋण के रूप में खुदरा बैंकिंग ने बैंकिंग ऋण संविभाग का वृद्धिशील हिस्सा आकर्षित किया।

आवास ऋण

3.12 राजकोषीय वर्ष 2003-04 में सकल गैर-खाद्य बैंक ऋण में आवास ऋण का अंश बढ़कर मार्च 2004 में 7.1 प्रतिशत हो गया, जो 2002-03 से एक प्रतिशत अंक अधिक है। यद्यपि, राजकोषीय वर्ष 2003-04 में आवास ऋण की वृद्धि दर 42 प्रतिशत पर काफी अधिक थी, लेकिन यह 2002-03 में दर्ज 55 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 13 प्रतिशत कम थी (बाक्स III.1)।

उपभोक्ता ऋण

3.13 फुटकर बैंकिंग संविभाग में विविध प्रकार के व्यक्तिगत उपभोग और निवेश प्रयोजन से व्यष्टियों को प्रस्तुत जमा और आस्ति संबद्ध उत्पाद और अन्य वित्तीय सेवाएँ शामिल हैं। बैंक फुटकर बैंकिंग को वृद्धि के लिए उपयुक्त आकर्षक बाजार खण्ड

बॉक्स III.1 : आवास वित्त

विकासशील देशों में आवास वित्त अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ उसके पश्चता और अग्रता संबंधों के कारण प्रायः सामाजिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है। भारत में कतिपय समर्थक नीतिगत उपायों पर्यवेक्षी प्रोत्साहन के कारण विगत वर्षों में आवास वित्त खण्ड में वृद्धि में तेजी आई है। रिज़र्व बैंक वृद्धिशील जमा संबंधी न्यूनतम संवितरण लक्ष्य और निम्नतर पूंजी पर्याप्तता अपेक्षा के द्वारा आवासीय क्षेत्र को बढ़ावा देता रहा है। 15 लाख रुपये तक आवासीय क्षेत्र को प्रदत्त प्रत्यक्ष वित्त प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का एक भाग माना जाता है। क्षतिग्रस्त आवास की मरम्मत के लिए आवास ऋण की सीमा बढ़ा कर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में 1 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2 लाख रुपये कर दिया गया है। बैंकों को आवासीय संपत्ति अर्जित करने के लिए व्यष्टियों को प्रदत्त ऋण के संबंध में उनके न्यूनतम मूल ऋण दर पर ध्यान दिए बिना ऋण दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता है।

भारत सरकार ग्रामीण इलाके में आवासीय क्षेत्र को काफी महत्त्व देता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक और गैर-कृषक दोनों के लिए आवास निर्माण व्यावसायिक और निवासीय आवश्यकता पूरी करता है जो समग्र ग्रामीण विकास की ओर ले जाता है। ग्रामीण आवासीय खण्ड के लिए संसाधन बढ़ाने में भारत सरकार, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय आवास बैंक और बैंकिंग क्षेत्र द्वारा किए जानेवाले प्रयास को बढ़ाने की दृष्टि से नाबार्ड ने अप्रैल 2001 से पात्र बैंकों को पुनर्वित्त बढ़ाने (निवेश ऋण) के लिए पात्र कार्यकलाप के रूप में ग्रामीण आवास निर्माण को शामिल करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में नये आवासीय निर्माण और मौजूदा आवास की मरम्मत/नवीकरण के लिए आवास वित्त उपलब्ध होता है, बशर्ते कि समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक / राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जमानती/मार्जिन अपेक्षा सहित विभिन्न शर्तें पूरी की जाएँ। यदि भूमि अर्जित की जाती है, तो भूमि लागत को मार्जिन मनी के रूप में माना जा सकता है। अन्यथा भूमि की लागत परियोजना लागत में शामिल नहीं की जाती है।

1993-2004 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के बकाया आवास ऋण में झुकाव दर में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो इसी अवधि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर-खाद्य ऋण की 14.8 प्रतिशत की झुकाव वृद्धि दर से अधिक है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल गैर-खाद्य ऋण में आवासीय ऋण का अंश 1992-93 के लगभग 3 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में लगभग 7 प्रतिशत हो गया।

अन्य अनेक देशों से भिन्न यहाँ आवासीय वित्त के कारण होनेवाली आस्ति हानि का अंश बहुत बहुत कम होता है। मार्चांत 2004 में हानि ऋण (अर्थात निवल एनपीए) बकाया अग्रिम का 1.4 प्रतिशत था। लेकिन, आवास वित्त बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से आस्ति गुणवत्ता और मूल मानकों पर इसके संभावित प्रभाव से चिंता बढ़ रही है। आवास क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर पर चिंता व्यक्त करते हुए रिज़र्व बैंक ने अस्थायी उपाय के रूप में जोखिम नियंत्रण

आवास ऋण का क्षेत्रवार आबंटन 2003-04

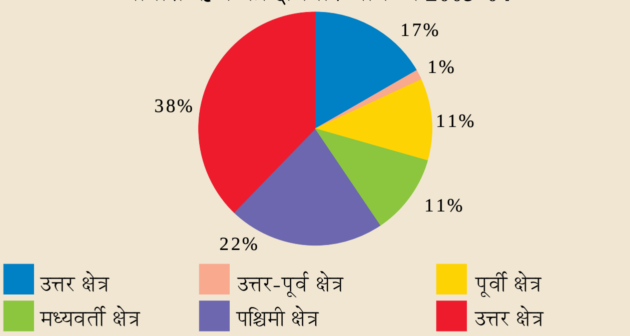

उपाय किये हैं तथा आवास ऋण के मामले में जोखिम भार 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया है।

हालाँकि 1990 के दशक के अंतिम वर्षों से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के आवास क्षेत्र ऋण में भारी वृद्धि हुई है। लेकिन गरीबों और निम्न आय वर्गों की आवासीय आवश्यकता अभी भी पूरी नहीं हुई है (ईपीडब्ल्यू, मई 2004)। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लगभग 90 प्रतिशत लोग आवास की कमी महसूस कर रहे हैं। कमजोर वर्ग को कम वित्तीयन का एक कारण मार्जिन की शर्त है। मार्जिन ऋण का वह अनुपात है, जो ऋणी द्वारा अपनी ओर से लाया जाता है। कमजोर वर्ग की आवासीय ऋण में पहुँच के लिए इस शर्त को एक बाधक तत्व समझा जाता है । इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक इंडिया मॉर्गेज क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन (आइएमसीजीसी) नामक एक अलग कंपनी का प्रवर्तन करने जा रहा है। आइएमसीजीसी ऋणदाता, अर्थात बैंक और आवास वित्त कंपनियों को ऋणी द्वारा मूलधन और ब्याज के भुगतान की गारंटी देगा। आइएमसीजीसी बैंकों और आवासीय कंपनियों के जोखिम बोध को भी कम करेगा तथा आवासीय क्षेत्र में ऋण बढ़ाने में उनकी सहायता करेगा। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी स्पष्ट हक की अनुपलब्धता और अनियमित आय स्थिति के कारण जोखिम मूल्यांकन में कठिनाई कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आवास वित्त की वृद्धि सीमित है।

संदर्भ :

इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल विकली, मई 2004

नाबार्ड - ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवास वित्त, 2003-04

भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2002-03

आवास वित्त संबंधी कार्यदल (अध्यक्ष : श्री आर.वी.वर्मा) 2002, राष्ट्रीय आवास बैंक

के रूप में देख रहे हैं। फुटकर बैंकिंग खण्ड के विस्तार का श्रेय उच्च प्रयोज्य आयवाले बढ़ते हुए मध्य वर्ग, बैंक द्वारा वित्तीयन के लिए उपलब्ध उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के व्यापक विकल्प, ऋण संस्कृति (क्रेडिट कार्ड) की बढ़ती हुई स्वीकार्यता और आकर्षक कर छूट से प्रेरित आवास ऋण की बढ़ती हुई मांग को दिया जा सकता है (बाक्स III.2)।

बाक्स III.2: उपभोक्ता ऋण

विगत वर्षों में पूरे विश्व में फुटकर ऋण वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय नवोन्मेष रहा है । फुटकर ऋण में विशेष प्रयोजन से दिए जानेवाले उपभोक्ता ऋण और सामान्य उपयोग के ऋण शामिल हैं। विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था में फुटकर खण्ड को दिए जानेवाले ऋण में वृद्धि का कारण वाणिज्यिक बैंकों का पारंपरिक बैंकिंग कार्यकलाप से आधुनिक व्यापक-आधारित ऋण संविभाग की ओर जाना रहा है। विशेषकर उभरती हुई अर्थव्यवस्था में फुटकर ऋण की वृद्धि का श्रेय सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र उन्नयन, वित्तीय बाजार सुधार के कारण विकसित होनेवाले समष्टि आर्थिक वातावरण और कतिपय व्यष्टि स्तरीय मांग और आपूर्ति के तत्व को दिया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी ने फुटकर ऋण की वृद्धि में योगदान किया है। प्रोद्योगिकी से उत्पन्न नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों ने बैंकों के तुलनपत्र और आय ढाँचे को सुदृढ़ करने में मदद की है। प्रौद्योगिकी ने ऋणियों के लिए बाह्य वित्त की लागत में सार्थक कमी की है, जबकि बैंक उत्पाद नवोन्मेष और वसूली, प्रसंस्करण से जुड़ी निम्नतर कारोबारी लागत और सूचना के उपयोग से लाभान्वित हुए हैं। इसके फलस्वरूप इसने बैंकों को जोखिम प्रबंध और उत्पादों के मूल्यन के लिए बेहतर तकनीक प्रदान की है।

तथापि, फुटकर ऋण की वृद्धि की कुछ सीमाएँ भी हैं। फुटकर ऋण निजी उपभोग बढ़ाने और मध्यम-दीर्घावधिक बचत बढ़ाने के साथ-साथ पारिवारिक ऋण ग्रस्तता को भी बढ़ा सकता है। फुटकर ऋण में तीव्र वृद्धि आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने के साथ-साथ निवेश कार्यकलाप के लिए दिए जानेवाले बैंक ऋण को भी अतिक्रमित कर सकता है। कतिपय विभिन्न वर्गीय अध्ययन द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि फुटकर ऋण बैंक की आस्ति गुणवत्ता को प्रभावित करने के साथ-साथ विभिन्न जोखिम भी उत्पन्न कर सकता है।

भारतीय संदर्भ में, फुटकर ऋण हाल के समय में बैंकों के लिए मुख्य आधार और लाभ का मुख्य प्रेरक रहा है तथा फुटकर संविभाग का अंश मार्च 2004 में कुल बकाया अग्रिम का 21.5 प्रतिशत था। फुटकर ऋण संविभाग की समग्र हानि 2.5 प्रतिशत रही और संपूर्ण ऋण संविभाग में सकल एनपीए के 7.4 प्रतिशत अनुपात की तुलना यह हानि पूर्णतः अनुकूल रही। फुटकर खण्ड में आवास ऋण का अंश कुल फुटकर संविभाग में लगभग 48 प्रतिशत था, जिसकी आस्ति हानि 1.9 प्रतिशत पर बहुत कम थी, जबकि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु खण्ड की आस्ति हानि 6.3 प्रतिशत पर सर्वाधिक थी। भारत में विशाखीकरण लक्ष्य के अलावा विभिन्न तत्वों ने फुटकर क्षेत्र को दिए जानेवाले बैंक ऋण को प्रभावित किया है। ये गिरती हुई ब्याज दर, सरकार द्वारा दिए जानेवाले राजकोषीय प्रोत्साहन, प्रतिभूतिकरण अधिनियम से संबंधित विभिन्न सुधारात्मक उपाय, शहरी भूमि हदबन्दी अधिनियम के निरसन और स्टाम्प शुल्क ढाँचे के युक्तिकरण, कंपनी चूक की कम दर वाणिज्यिक और कंपनी क्षेत्र से ऋण का कम उठाव गृह-निर्माण लागत में कमी प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्त टिकाऊ वस्तुओं और आटोमोबाइल की लागत में कमी, और क्रेडिट/डेबिट कार्ड[3], एटीएम प्रत्यक्ष नामे और फोन बैंकिंग, आदि के बढ़ते हुए उपयोग से संबंधित प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष से संबंधित हैं। चूँकि फुटकर बैंकिंग पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न रूप में (उदाहरणार्थ, सहकारी बैंक, जिनमें से कुछ शताब्दी पुराने हैं, हमेशा फुटकर बैंकिंग करते रहे हैं) हमेशा प्रचलित रहा है इसलिए यह अनेक बैंकों के लिए बैंकिंग की मुख्य धारा का पर्याय हो गया है। हालाँकि निजी क्षेत्र की नयी पीढ़ी के बैंकों (आइसीआइसीआइ बैंक, जिनका घरेलू फुटकर वृद्धि में लगभग 30 प्रतिशत अंश है) ने फुटकर ब्रांड के निर्माण और उन्हें बरकरार रखने के लिए निवेश किया है, जिसमें अपेक्षित प्रौद्योगिकीय और कर्मचारी तंत्र का समर्थन भी मिला है, लेकिन उनके प्रतिपक्षी सरकारी क्षेत्र के बैंक भी उनसे पीछे नहीं हैं। भारतीय स्टेट बैंक जिसका फुटकर खण्ड उसके कुल अग्रिम का 20 प्रतिशत है जैसे सरकारी क्षेत्र बैंकों ने अपनी विशाल शाखा नेटवर्क और विस्तार को सुदृढ़ करने के लिए फुटकर खण्ड का बड़ा भाग पाने के लिए जोरदार ढंग से मैदान में कूद पड़े हैं। भारतीय स्टेट बैंक के फुटकर ऋण में 8,803 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि (पिछले वर्ष 6,641 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई थी। अतः मुद्दा यह है कि क्या ऋण तक पहुँच बढ़ाने व्यापक प्रवर्तन के लिए एक सक्षम चैनल के रूप में फुटकर ऋण उभर कर आ चुका है। इस समय, फुटकर ऋण मोटे मौर पर शहरी और महानगरी क्षेत्रों में ही केन्द्रित है।आवास और उपभोक्ता ऋण क्षेत्र में हुई उच्च वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए, अस्थायी उपाय के रुप में रिजर्व बैंक ने जोखिम नियंत्रण उपाय किए है तथा वैयक्तिक ऋण और क्रेडिट कार्ड सहित उपभोक्ता ऋण के मामले में जोखिमभार 100 से प्रतिशत से बढ़कर 125 प्रतिशत कर दिया है (वार्षिक नीति की मध्यवधि समीक्ष, 2004-05)

बैंकों का फुटकर संविभाग
(मार्च 2004 के अंत की स्थिति)

मद	बकाया राशि (करोड़ रुपये में)	बकाया ऋण में ऋण हानि का प्रतिशत	बकाया ऋण में निवल एनपीए का प्रतिशत
(i) आवास ऋण	89,449	1.9	1.4
(ii) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ	6,256	6.6	4.0
(iii) क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशि	6,167	6.3	2.4
(iv) अन्य वैयक्तिक ऋण	87,170	2.6	1.6
(v) कुल फुटकर ऋण [(i) +(ii)+(iii)+(iv)]	1,89,041	2.5	1.6
(vi) कुल ऋण और अग्रिम	8,59,092	7.4	2.8

आंकड़े घरेलू परिचालनों से संबंधित है।
स्रोत : आरबीआइ परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणी

संदर्भ :

सेलिन, जी.एल. एंड अर्लैंड एन. (2004), द इकोनॉमिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग - एन इम्पीरिअल एनालाइसिस ऑफ द यूके मार्केट फॉर पर्सनल करेंट एकाउंट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, बैंक आफ इंग्लैंड।

यूरोपियन क्रेडिट रिसर्च इंस्टीट्यूट (2000), कंज्यूमर क्रेडिट इन द यूरोपियन यूनियन इसीआरआइ रिसर्च रिपोर्ट नं. 1 फरवरी ।

मोरिस, जे, (2001), रिस्क डाइवर्सिफिकेशन इन क्रेडिट पोर्टफोलियो, एनओवरव्यू ऑफ कंर्टी प्रैक्टिसेस, आइएमएफ, डब्ल्यूपी नं.01/2000

स्टेफनी के. एंड हेराल्ड एस. (2002) कंज्यूमर क्रेडिट रेट्स इन द यूरोजोन : एविडेन्स ऑन द इमर्जेंस ऑफ ए सिंगल रिटेल बैंकिंग मार्केट, ईसीआरआइ रिसर्च रिपोर्ट नं.2, जनवरी।

वेन्डी इ. (2004) टेस्टिंग फॉर एडवर्स सेलेक्सशन एंड मोरल हेजार्ड इन कंज्यूमर लोन मार्केटस, फेडरल रिजर्व बोर्ड, फरवरी 10।

विटमैन, जे. (1980), कंज्यूमर लेंडिंग द कनाडियन बेंकर एंड आइसीबी रिव्यू टोरंटो : अगस्त , खण्ड 87, अंक 4, पृष्ठ 28।

[3] अध्याय II: बाक्स II.17. भी देखें।

3.14 फुटकर बैंकिंग खण्ड में प्रस्तुत किए जानेवाले विशेष उत्पाद आवास ऋण, टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए उपभोग ऋण, ऑटो ऋण, क्रेडिट कार्ड और शैक्षिक ऋण हैं। ऋण का विपणन बैंकों द्वारा प्रस्तुत उत्पाद में अंतर करने के लिए आकर्षक ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ऋण का मूल्य 20 हजार रुपये से लेकर 100 लाख रुपये तक के बीच विशेष रेंज में हो सकता है। सामान्यतः ऋण की अवधि 5 से 7 वर्ष की होती है और आवास ऋण 15 वर्ष की लंबी अवधि के लिए मंजूर किए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड इस उत्पाद समूह का तेजी से बढ़नेवाला दूसरा उपखण्ड है।

3.15 फुटकर बैंकिंग की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता अपेक्षया निम्न मूल्य का ऋण है। ऐसे ऋण के मूल्यांकन के लिए बैंक अधिक परिष्कृत मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। इनमें साख दर-निर्धारण तकनीक आवेदन का स्वतः कार्रवाई, व्यवहार संबंधी दर निर्धारण मॉडल और आय प्रतिनिधि मॉडल शामिल हैं (बॉक्स III.3) इसके अलावा, बैंक ग्राहकों के चयन में सुधार करने और ऋण हानि कम करने के उपाय के रूप में आँकड़ा हिस्सेदारी का भी उपयोग करते हैं। संपूर्ण ऋण कार्यालय के अभाव में नकारात्मक आँकड़ा हिस्सेदारी बैंकों को अपनी आंतरिक काली सूची का उपयोग करने के अलावा अत्यधिक उपयोग में लाए जानेवाले क्रेडिट कार्डों के आँकड़ों की हिस्सेदारी भी प्रदान करती है।

निर्यात ऋण

3.16 2003-04 में निर्यात ऋण में 2002-03 में हुई 15 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2003-04 में निवल बैंक ऋण में निर्यात ऋण का अंश 2002-03 के 7.4 प्रतिशत की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष में उच्चतर निर्यात वृद्धि के बावजूद 2003-04 में थोड़ा-सा बढ़कर 7.6 प्रतिशत हुआ (चार्ट III.2) निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा मई-नवंबर 2003 के दौरान अधोगामी प्रवृत्ति दिखाती है परिशिष्ट सारणी III.4। 2003-04 के दौरान उपयोग में लाया गया बकाया निर्यात ऋण पुनर्वित्त नगण्य रहा।

उद्योग-वार ऋण का अभिनियोजन

3.17 2003-04 में औद्योगिक ऋण में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2002-03 में हुई 13.6 प्रतिशत की वृद्धि से कम थी। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा ऋण का उठाव कंपनी क्षेत्र द्वारा वित्तीयन के आंतरिक संसाधनों और बाह्य वाणिज्यिक ऋण का अधिकाधिक सहारा लेने के साथ-साथ औद्योगिक कार्यकलाप में उछाल और सुदृढ़ कंपनी तुलन-पत्र के बावजूद अपेक्षया कम हुआ। मौजूदा क्षमता अधिक्य के कारण निर्धारित निवेश के वित्तीयन के लिए ऋण की मांग निम्नतर रही। फिर भी, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में

बॉक्स III.3: साख दर-निर्धारण

सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र उन्नयन ने बैंकों को अपने ऋण संविभाग के जोखिम का बेहतर प्रबंध करने में सूचना प्रसंस्करण और वित्तीय इंजीनियरिंग के विभिन्न परिष्कृत साधन अपनाने के लायक बना दिया है। साख दर निर्धारण ऐसी तकनीकों में से एक है, जिसका बैंकों द्वारा अधिकाधिक उपयोग सूचना की दृष्टि से अपारदर्शी ऋणियों को मूल्यांकन करने के लिए किया जा रहा है। विभिन्न देशों के साक्ष्य बताते हैं कि संयुक्त राज्य में 75 प्रतिशत से अधिक बंधक ऋण देने वाले और 90 प्रतिशत से अधिक क्रेडिट कार्ड देनेवाले ऋण देने से संबंधित निर्णय लेते समय साख दर का उपयोग करते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में बैंकों ने बड़े पैमाने पर विशेषकर, आवास ऋण और क्रेडिट कार्ड सहित फुटकर ऋण के लिए साख दर-निर्धारण तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

साख दर मुख्यतः वह सांख्यिकीय संख्या है, जो ऋणियों से जुड़े जोखिम के स्तर की ओर संकेत करता है। उच्चतर/निम्नतर साख दर ऋणियों के निम्नतर/उच्चतर जोखिम स्तर का संकेतक होता है। बैंक जोखिम आधारित मूल्यन रणनीति के लिए साख दर का उपयोग करते हैं, जो ऋणियों की ऋण स्थिति और ऋण पात्रता पर आधारित विभेदक ब्याज दर और अन्य ऋण शर्तों के लिए अनिवार्य होती है।

बैंक और वित्तीय संस्थाएँ ऋण पात्रता के विश्लेषण के लिए अनेक प्रकार के साख दर-निर्धारण मॉडल का उपयोग करते हैं। ऋण सूचना एजेंसियाँ विविध प्रयोजनों के लिए अलग-अलग दर-निर्धारण मॉडल का उपयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, आवास वित्त और कार ऋण के मामले में व्यक्तिगत उपभोग सहित क्रेडिट कार्ड और अन्य फुटकर ऋण से भिन्न अलग मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। अभी भी ऋण सूचना एजेंसियों के लिए सामान्यतः व्यष्टियों को साख-दर प्रदान करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। फिर भी, कुछेक ऋण सेवा कंपनियाँ अब इनमें सुधार लाने के लिए शुल्क लेकर साख दर और परामर्शी सेवा बेच रही हैं।

साख दर-निर्धारण मॉडल में ऋणियों की साख-रिपोर्ट, भुगतान इतिवृत्त और ऋण आवेदन पत्रों तथा वसूली, प्रतिबंध, कानूनी मुकदमे और अन्य वसूली मदों से छाँटी गई अनेक प्रकार की सूचनाओं को लेकर तैयार किए गए जटिल सूत्र का उपयोग किया जाता है। दर-निर्धारण मॉडलों में विशेषकर ऋणियों के व्यवसाय, सेवा-अवधि, मकान और कार सहित आस्ति स्वामित्व, जमा और नामे राशि, ऋण के प्रकार, नया ऋण और जमा चेक की संख्या और अनेक अन्य बातों के साथ-साथ इन संबंधी सूचना का उपयोग किया जाता है।

साख दर-निर्धारण मॉडलों में काफी समय से उपयोग की गई सूचना के प्रकार और ऋणियों के जोखिम के मानदण्डों से संबंधित गोपनीय बातों और अनुषंगी विवादों के बारे में गोपनीयता बरती जा रही है। ऋणदाता के परिप्रेक्ष्य में, प्रकटीकरण और पारदर्शिता की सीमा से संबंधित अनेक समस्याएँ होती हैं। दूसरी ओर, ऋणी के परिप्रेक्ष्य में, आँकड़ों की सुरक्षा से संबंधित कानूनी समस्याएँ होती हैं।

संदर्भ :

बर्गर, ए.एन., फ्रेम, डब्ल्यू.एस. और मिलर, एन.एच (2002), 'क्रेडिट स्कोरिंग एण्ड एवलेब्लिटी, प्राइज एण्ड रिस्क ऑफ स्मॉल बिजनेस क्रेडिट' फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ अटलांटा, वर्किंग पेपर 2002, 06 अप्रैल।

फ्रेम. डब्ल्यू.एल. श्रीनिवासन, ए और वुस्की.एल, (2002) दि एफेक्ट ऑफ क्रेटिंग ऑन स्माल बिजनेस लेंडिंग, जनरल ऑफ मनी एण्ड बैंकिंग वॉ. 33 (3)।

हेंड, डी.जे एण्ड हैके, डब्ल्यू.इ. (1997), स्टैटिस्टकल क्लासीफिकेशन मेथड्स इन कंज्यूमर क्रेडिट स्कोरिंग : ए रिव्यू, 'जर्नल ऑफ रॉयल स्टैटिस्टकल सोसायटी, वॉल 160।

मेस्टर.एल (1997)), ह्वाट इज द प्वाइंट ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ फिलाडल्फिया बिजनेस रिव्यू, सितंबर/अक्तूबर।

चार्ट III.2: भारत का निर्यात और निर्यात ऋण

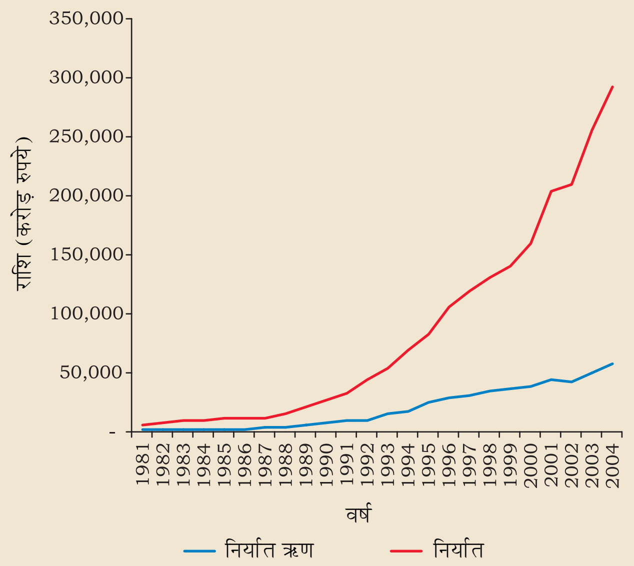

चार्ट III.3: सकल बैंक ऋण का उद्योगवार अभिनियोजन

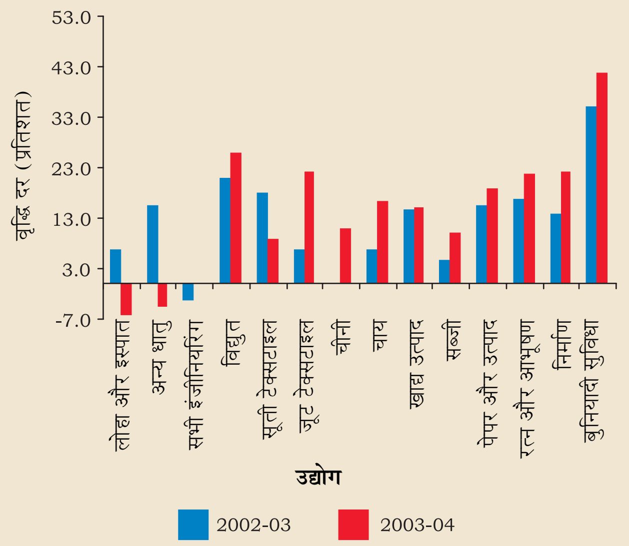

गैर-खाद्य ऋण की वृद्धि के तरीके में स्पष्ट परिवर्तन हुआ। बैंक ऋण का उद्योगवार अभिनियोजन बुनियादी क्षेत्र, कृषि आधारित उद्योग, निर्यात, थोक व्यापार और पर्यटन उद्योग को प्रदत्त ऋण से प्रभावित रहा। पावर दूर संचार, सड़क और पत्तन सहित बुनियादी क्षेत्र को हुए ऋण प्रवाह में सर्वाधिक वृद्धि हुई। 2003-04 में तीन बुनियादी खण्डों - बिजली, दूर संचार तथा सड़क और पत्तन - में ऋण की भारी वृद्धि होने से बुनियादी क्षेत्र को हुए ऋण के प्रवाह में 41.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। चीनी, चाय, वानस्पतिक तेल, कागज, रबर और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जैसे कृषि आधारित उद्योगों में ऋण के प्रवाह में वृद्धि हुई। 2003-04 में अन्य जिन क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह में वृद्धि हुई, वे बिजली, तंबाकू उत्पाद, 'रत्न और आभूषण' तथा निर्माण और ऑटोमोबाइल थे (चार्ट III.3, परिशिष्ट सारणी III.5)।

रुग्ण / दुर्बल उद्योगों को बैंक ऋण

3.18 हाल के वर्षों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वित्तपोषित रुग्ण लघु उद्योगों और गैर लघु उद्योगों (रुग्ण/दुर्बल) की संख्या कम हुई है। रुग्ण/दुर्बल उद्योगों में अवरुद्ध हुए बैंक ऋण की मात्रा मार्च 2002 के अंत के 26,065 करोड़ रुपये से बढ़कर 33.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कराते हुए मार्च 2003 के अंत में 34,816 करोड़ रुपये हो गई। कुल बैंक ऋण में रुग्ण इकाइयों के ऋण का अंश मार्च 2002 के अंत के 4.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 4.8 प्रतिशत हो गया। कुल रुग्ण ऋणों में बड़ा भाग विभिन्न श्रेणी की रुग्ण इकाइयों, गैर लघु उद्योग और गैर लघु इकाइयों का था जिनके बाद रुग्ण लघु उद्योग और गैर लघु उद्योग दुर्बल इकाइयों का स्थान है (परिशिष्ट सारणी III.6)।

संवेदनशील क्षेत्र को उधार

3.19 2003-04 के दौरान पूंजी बाजार, स्थावर संपदा और पण्य क्षेत्र को दिए बैंक उधार में भारी वृद्धि हुई। तथापि, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का संवेदनशील क्षेत्र के प्रति ऋण जोखिम कुल बैंक ऋणों व अग्रिमों का मात्र 3 प्रतिशत था। पूंजी बाजार को दिए गए बैंक उधार नाममात्र ही अर्थात बकाया ऋणों व अग्रिमों के 0.4 प्रतिशत ही रहे। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋणों व अग्रिमों में स्थावर संपदा और पण्य क्षेत्र को दिए गए ऋण का भाग क्रमशः 1.6 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत था। संवेदनशील क्षेत्रों के कुल ऋणों में 51.6 प्रतिशत भाग के साथ स्थावर संपदा क्षेत्र सबसे आगे था जिसके बाद क्रमशः पण्य क्षेत्र और पूंजी बाजार थे (सारणी III.7 तथा परिशिष्ट III.7)। बैंक समूहों में, संवेदनशील क्षेत्रों को दिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल ऋण जोखिम का लगभग 60 प्रतिशत लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बना रहा।

अन्य निवेश

3.20 ऋणों और अग्रिमों के अलावा, बैंक कम्पनी क्षेत्र को गैर - एसएलआर निवेश के रूप में भी वित्तीय समर्थन प्रदान करते हैं जिनमें निजी कम्पनी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र, शेयर, बांड और डिबेंचर शामिल हैं (सारणी III.8)। बांड और डिबेंचरों में निवेश बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश का प्रमुख घटक

सारणी III.7: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

(मार्च की समाप्ति पर) (राशि करोड़ रुपये में)

निम्न को अग्रिम	2003	2004
	1	2
1. पूंजी बाजार क्षेत्र	2,484 (10.5)	3,333 (12.2)
2. स्थावर संपदा क्षेत्र	12,464 (52.6)	14,170 (51.6)
3. पण्य क्षेत्र	8,735 (36.9)	9,952 (36.2)
कुल (1+2+3)	**23,683 (100.0)**	**27,455 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत है।

बना रहा, हालांकि बैंकों के कुल गैर-एसएलआर निवेश में इसका अंश वर्ष के दौरान कुछ गिरा। यह गिरावट, कम्पनियों के, के सुदृढ़ तुलन-पत्र तथा निधियों के आन्तरिक स्रोतों का अधिकाधिक सहारा लेने के कारण हो सकती हो। 2003-04 के दौरान पारस्परिक निधियों को बैंकों के वित्त पोषण में तेज वृद्धि हुई। कुल गैर-एसएलआर निवेश में पारस्परिक निधियों में बैंक के निवेशों का अंश 2002-03 के 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 8.6 प्रतिशत हो गया।

जमा प्रमाण पत्र (सीडी)

3.21 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी जमाप्रमाण-पत्रों की बकाया राशि 4 अप्रैल 2003 के 1,188 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2004 के मध्य में 4,461 करोड़ रुपये की हो गयी (परिशिष्ट सारणी III.8)। 3 माह की परिपक्वता वाले जमाप्रमाण पत्रों के लिए विशिष्ट बट्टादर अप्रैल 2003 के मध्य के 7.2 प्रतिशत से गिरकर अगस्त 2003 के अंत में 5.5 प्रतिशत तथा मार्च 2004 के मध्य में और गिरकर 5.0 प्रतिशत रह गयी। 2004-05 के दौरान (15 अक्तूबर 2004 तक) यह और कम होकर 4.75 प्रतिशत रह गयी। 15 अक्तूबर 2004 तक जमा प्रमाण पत्रों की बकाया राशि बढ़ती हुई 4,837 करोड़ रुपये की हो गयी। जमा प्रमाण-पत्रों की यह वृद्धि अनेक कारणों से हुई है, जिनमें गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में बैंकों द्वारा निवेशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिशा निदेश जारी करना, 1 मार्च 2004 से जमाप्रमाणपत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी करना, जमा प्रमाण पत्रों के अंतर्गत जमाराशियों की परिपक्वता-पूर्व आहरण की छूट का न होना, तथा द्वितीयक बाजार में लेनदेने के लिए बेहतर सुविधाओं मौजूद होना हैं। इन गतिविधियों ने पारस्परिक निधियों द्वारा विशेषकर उनकी बेहतर निधियों की स्थिति के कारण, जमाप्रमाण प्रत्रों में निवेश के लिए ज्यादा मांग बढ़ा दी। एक उत्साहजनक गतिविधि यह भी रही कि कुछ सर्वोच्च रैंकिंग वाले बैंक अपने जमा प्रमाण पत्रों की रेटिंग करा रहे हैं ताकि वे बाजार में बेहतर पहुंच बना सकें, हालांकि विद्यमान दिशानिदेशों में ऐसा कराना आवश्यक नहीं है।

सारणी III.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्र को उधार

(मार्च की समाप्ति पर) (Rs. crore)

	लिखत	2003	2004
	1	2	3
1.	वाणिज्यिक पत्र	4,007 (3.0)	3,770 (2.7)
2.	यूटीआई और अन्य मुचुअल फंडों की यूनिटें	6,317 (4.7)	11,808 (8.6)
3.	निम्नलिखित द्वारा जारी शेयरों में निवेश	10,206 (7.6)	9,696 (7.0)
	जिसमें से:		
	क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,430 (1.1)	1,272 (0.9)
	ख) निजी कंपनी क्षेत्र	7,589 (5.7)	7,395 (5.4)
4.	निम्नलिखित द्वारा जारी बाण्डों/डिबेंचरों में निवेश	1,13,169 (84.6)	1,12,370 (81.6)
	जिसमें से:		
	क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	46,854 (35.0)	48,646 (35.3)
	ख) निजी कंपनी क्षेत्र	32,973 (24.7)	27,903 (20.3)
कुल	**(1+2+3)**	**1,33,699 (100.0)**	**1,37,644 (100.0)**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल के प्रति प्रतिशत हैं।
2. आंकड़ों में आरआरबी सम्मिलित नहीं है । आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों पर आधारित हैं।

वाणिज्यिक पत्र (सीपी)

3.22 सहज चलनिधि की स्थितियों ने कम्पनियों को वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए प्रेरित किया। वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम ने नवम्बर 2003 के मध्य से गति पकड़ी जिसका कारण था जमा प्रमाण-पत्रों तथा वाणिज्यिक पत्रों को छोड़कर एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश पर प्रतिबंध लगाने संबंधी रिज़र्व बैंक के दिशा-निदेशों के संदर्भ में पारस्परिक निधियों और बैंकों द्वारा वाणिज्यिक पत्रों में बढ़ी हुई रुचि। इसके अलावा वाणिज्यिक पत्रों पर स्टाम्प डयूटी में कटौती से भी इसके बाजार में उछाल आया। वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टा दरों को अप्रैल 2003 के प्रारम्भ के 5.25 - 8.15 प्रतिशत के दायरे से घटाकर मार्च 2004 के अंत में 4.70 - 6.50 प्रतिशत के दायरे में ला दिया गया। 2004-05 के दौरान (नवम्बर 2004 के मध्य तक) ये बट्टा दरें और कम होकर 5.10 - 6.23 प्रतिशत पर आ गयीं। भारित औसत बट्टा दर भी अप्रैल 2003 के प्रारम्भ के 6.20 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2004 के अंत तक 5.11 प्रतिशत रह गया तथा नवंबर 2004 के पहल में बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गया । प्रमुख साख दर वाली और मध्यम साख दर वाली कम्पनियों के बीच भारित औसत बट्टा दर का दायरा अप्रैल 2003 के अंत के 162 आधार बिन्दुओं से घटकर मार्च 2004 के अंत में 73 आधार बिन्दुओं तक आ गया, परन्तु नवंबर 2004 के मध्य तक और कम होकर 30 आधार अंक तक पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान नवंबर 2004 के मध्य तक वाणिज्यिक पत्र की सबसे ज्यादा चाही गयी परिपक्वता अवधि '90 दिनों तक' तथा '181 दिन और उससे अधिक' की थी। चालू वित्त वर्ष में (नवंबर 2004 के मध्य तक) वाणिज्यिक पत्रों की एकत्रित राशि में विनिर्माण और अन्य कम्पनियों का 40 प्रतिशत पर निम्नतर था (2003-04 में यह 44 प्रतिशत था) जबकि वित्त/पट्टादारी कम्पनियों तथा वित्तीय संस्थाओं का अंश 2003-04 के 38 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 55 प्रतिशत और 5 प्रतिशत हो गया।

वायदा दर करार (एफआरए) ब्याज दर स्वैप (आइआरएस)

3.23 चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक एफआरए और आइआरएस बाजार की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है। एफआरए / आइआरएस लेनदेन, करारों की संख्या तथा बकाया सांकेतिक मूलधन राशि दोनों दृष्टियों से, 4 अप्रैल 2003 के 2,42,983 करोड़ रुपयों के 9,363 संविदाओं से बढ़कर 19 मार्च 2004 को 5,18,260 करोड़ रुपये के 19,867 संविदाओं तक पहुंच गये। 2004-05 के दौरान संविदाओं की संख्या तथा बकाया राशि 15 अक्तूबर 2004 को समाप्त पखवाड़े में बढ़कर क्रमशः 30,101 तथा 7,99,302 करोड़ रुपये की हो गयी। संविदाओं की संख्या और राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही बाजार में सहभागिता भी व्यापक आधार वाली रही है और इसमें चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्राथमिक व्यापारी, विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश संविदाओं में एनएस ई-मिबोर और मि फोर को आधार दरों के रूप में प्रयुक्त किया गया। प्रयुक्त अन्य आधार दरें थीं - 1 वर्ष की अवशिष्ट मीयादवाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर द्वितीयक बाजार की आय, 364 दिवसीय खज़ाना बिलों पर प्राथमिक उच्चतम आय आदि।

सरकार को ऋण

3.24 हाल के वर्षों में सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवेश अपेक्षित सांविधिक चलनिधि अनुपात, जो 25 प्रतिशत है, से काफ़ी अधिक रहा है। मार्च 2004 के अंत की स्थिति के अनुसार सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों में निवेश बैंकों के निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 41.3 प्रतिशत था जो मार्च 2003 के अंत में 41.5 प्रतिशत था।

3.25 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश विस्तार की दर राजकोषीय वर्ष 2003-04 में 21.2 प्रतिशत थी जो 2002-03 की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत अंक कम था। सरकारी प्रतिभूतियों में निजी क्षेत्र के बैंकों का निवेश 2002-03 के 16.5 प्रतिशत की तुलना में 2003-04 में 31.5 प्रतिशत बढ़ा । निजी क्षेत्र के बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बढ़ती हुई वरीयता से पूंजी के प्रति जोखिम भारित आस्ति अनुपात में सुधार के लिए उनके प्रयास परिलक्षित होते है। विदेशी बैंकों के निवेश में 2002-03 के 27.6 प्रतिशत की तुलना में 2003-04 में 6 प्रतिशत की बहुत ही कम वृद्धि दर्ज की गयी।

ऋण-जमा अनुपात

3.26 उत्पादक क्षेत्र को बढ़ावा देने और आर्थिक वृद्धि में योगदान करने में बैंकों की भूमिका के विश्लेषण के लिए व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाने वाले बैंकिंग संकेतकों में से एक है ऋण जमा अनुपात (सी-डी अनुपात)। बैंक आधारित वित्तीय प्रणाली में, ऋण सुपुर्दगी प्रणाली की प्रभावशीलता जानने के लिए समग्र उपाय के रूप में सी-डी अनुपात अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है। उच्च सी-डी अनुपात का अर्थ है बैंकों की अधिक ऋण उन्मुखता। तथापि, भारतीय संदर्भ में, सी-डी अनुपात ने गत कुछ वर्षों में अधोगामी प्रवृत्ति दिखायी है। यद्यपि ऋण का अभिनियोजन और सी-डी अनुपात का समय-पण्य सामान्यतः अर्थव्यवस्था के स्वरूपगत रुपांतरण से

प्रभावित हैं, तथापि ऋण संस्कृति और बैंकों की उधार नीति का अनुपात के आकार पर सहज प्रभाव होता है (बाक्स III.4)।

3.27 बेसिक स्टॅटिस्टिकल रिटर्नस (बीएसआर) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का मार्च 2004 के अंत का सी-डी अनुपात (मंजूरी के अनुसार) 58.7 प्रतिशत था जबकि मार्च 2003 में यह 59.2 प्रतिशत था। जमा के प्रति ऋण और निवेश अनुपात (आइ सी-डी) (उपयोगितानुसार) में परिलक्षित संसाधनों का कुल प्रवाह मार्च 2002 अंत के 65.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 66.4 प्रतिशत हो गया। पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र के लिए क्षेत्रवार ऋण-जमा अनुपात (मंजूरी अनुसार) में वृद्धि देखी गयी (परिशिष्ट सारणी II.9)

3.28 सी-डी अनुपात समग्र उपाय के रूप में उपयोगी होने के बावजूद बैंकों के ऋण उन्मुखीकरण और बैंक ऋण में विविध आर्थिक एजेंटों की पहुंच की सीमित जानकारी ही उपलब्ध कराता है। इस संदर्भ में, ऋण सुपुर्दगी प्रणाली की प्रभावशीलता जानने और नीति प्रतिपादन हेतु महत्त्वपूर्ण जानकारी की निविष्टि उपलब्ध कराने के लिए ऋण बाजार संकेद्रण के वैकल्पिक उपायों की खोज हेतु अनेक अध्ययन किए गए हैं (बाक्स III.5)।

प्रमुख बैंकिंग संकेतकों की प्रवत्तियां 2004-05

3.29 2004-05 के दौरान (29 अक्तूबर 2004 तक) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण 7.5 प्रतिशत (आइडीबीआइ रुपांतरण को घटाकर 7.2 प्रतिशत) बढ़ गया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 9.0 प्रतिशत की वृद्धि से उच्चतर था। इस वर्ष जमाराशि निम्नतर वृद्धि मुख्यत: बैंकिंग प्रणाली में अनिवासी भारतीय को जमाराशि में कमी के कारण थी। तथापि, वार्षिक आधार पर कुल जमाराशियों में 15.8 प्रतिशत वृद्धि (आइडीबीआइ के रुपांतरण को घटाकर 15.6 प्रतिशत) 2003-04 के दौरान 11.8 प्रतिशत की वद्धि से उच्चतर थी। 2004-05 के दौरान (29 अक्तबर तक) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण में 17.5 प्रतिशत (आइडीबीआइ के रुपांतरण को घटाकर 13.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो 2003-04 की इसी अवधि में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि से काफी अधिक थी। खाद्य ऋण में 3,757 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 13,459 करोड़ रुपए की गिरावट आयी थी जो 17,210 करोड़ रुपए का सुधार दर्शाता है। 2004-05 के दौरान (29 अक्तूबर तक) गैर-खाद्य ऋण में 17.9 प्रतिशत आइडीबीआइ रुपांतरण को घटातक 13.8 प्रतिशत

बाक्स III.4 : ऋण संस्कृति

इस बात की मान्यता बढ़ती जा रही है कि यद्यपि समष्टिगत अर्थ व्यवस्था की स्थिरता आवश्यक है, तथापि निरंतर और तेज आर्थिक प्रगति हेतु अनेक पर्याप्तता की स्थितियां महत्त्वपूर्ण होती हैं (आइएमएफ, 2003)। जहां तक पर्याप्तता स्थितियों के विभिन्न संकेतकों का प्रश्न है, अर्थशास्त्री प्रभावी ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को बेहद महत्त्व देते हैं जो विभिन्न उत्पादक गतिविधियों हेतु ऋण तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करती है। लगभग दो दशक पहले अनेक देशों के बीच यह माना जाता था कि औपचारिक ऋण संस्थाओं के व्यापक जाल के माध्यम से ऋण तक बेहतर पहुंच बनायी जा सकती है। 1990 के दशक में, अर्थशास्त्रियों ने औपचारिक ऋण संस्थाओं के कार्य निष्पादन से और अनौपचारिक ऋण एजेंसियों की निरंतर मौजूदगी का अध्ययन किया। नीति निर्माताओं ने इस बात को मान्यता दी है कि उपर्युक्त ऋण संस्कृति से भी ऋण तक पहुंच बनायी जा सकती है।

अब धारणात्मक रूप से, बैंकों ने चार मूल प्रकारों की ऋण संस्कृति अपनायी है। ये निम्नलिखित से संबंधित हैं : मूल्य-प्रेरित, तत्काल कार्य-निष्पादन प्रेरित, उत्पादन-प्रेरित और ध्यान न दी गई ऋण संस्कृति। सामान्यतः, किसी बैंक की ऋण संस्कृति के मुख्य निर्धारक होते है शीर्षस्थ प्रबंधन तंत्र की प्रतिबद्धता, ऋण अनुशासन, प्राथमिकता आधारित प्रोत्साहन, कारोबार की जोखिम प्रबंधित दिशा और साथ ही स्पष्ट, निरंतर और सरल संप्रेषण नीति। प्रभावी ऋण सुपुर्दगी प्रक्रिया में प्राथमिकताओं की क्रमबद्धता और समेकन की प्रक्रिया, संस्कृति, नीति और नियंत्रण आवश्यक होता है। यह कंपनी प्राथमिकताओं के निर्धारण, ऋण संस्कृति के चुनाव, ऋण जोखिम नीति का निर्धारण और जोखिम नियंत्रण लागू करके किया जा सकता है (स्ट्रीस्चेक, 2003)। प्रतिस्पर्धी वातावरण में, ऐसी नीति बतलाती है कि ऋण संस्कृति का स्वरूप स्थिर न होकर गतिशील होना चाहिए।

भारतीय संदर्भ में, ऋण संस्कृति के मसले पर रेड्डी (2004) और मोहन (2003, 2004) के कारण काफी चर्चा हुई। बैंक उधार नीति से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच ने यह दिखाया है कि बैंकों को चाहिए कि वे प्रभावी ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में अपना योगदान देने के लिए जोखिम से बचने की नीति अपनाने के बजाए विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीति अपनाएं। व्यापक रूप से, ऋण-जमा अनुपात और ग्रामीण ऋण, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश उधार दरों का अधोगामी बना रहना, अन्य अनेक गतिविधियों के बीच श्रेणी वार उधार नीति की मौजूदगी संबंधी चिंताओं के बीच ऋण संस्कृति पर चर्चा उभर कर आयी है। इस संदर्भ में अध्ययनों से यह सुझाव प्राप्त हुए हैं कि बैंकों को क्रमिक अविनियमन और वित्तीय बाजार में किए जाए सुधार की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उधार नीति बनानी चाहिए।

संदर्भ :

मोहन, राकेश (2003), 'भारतीय बैंकिंग का रुपांतरण : बेहतर कल की तलाश में', भारिबैंक, 'भाषण, भारिबैंक बुलेटिन, जनवरी'।

मोहन, राकेश (2004), 'औद्योगिक विकास हेतु वित्त', भारिबैंक बुलेटिन, भाषण लेख, मार्च।

'भारतीय सुस्त बैंकर बांडों की ओर आकर्षित, टाईम्स समाचार नेटवर्क, 25 नवम्बर 2003।

वाइ.वी.रेड्डी (2004), 'ऋण नीति, प्रणाली और संस्कृति', भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, मार्च।

देव स्ट्रीस्चेक (2003), ञ्ऋण संस्कृति भाग II : ऋण संस्कृति के प्रकार, दिनांक आरएमए जर्नल, फिलाडेल्फिया : दिसम्बर 2002/ जनवरी 2003, खण्ड 85, आइएसएस 4, पृष्ठ 35

की सुदृढ़ वृद्धि हुई जबकि 2003-04 वर्ष की इसी अवधि में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2004-05 के दौरान (29 अक्तूबर तक) वर्धमान गैर-खाद्य ऋण-जमा अनुपात काफी अधिक 127.8 प्रतिशत (आइडीबीआइ के रुपांतर को घटाकर 102 प्रतिशत) था जो 2003-04 की इसी अवधि में यह 41 प्रतिशत था।

बाक्स III.5: ऋण बाजार संकेंद्रण

वित्तीय साहित्य के अनुसार ऋण संविभाग जोखिम कम करने, आस्ति गुणवत्ता सुधारने और उत्पादक कार्यों हेतु संसाधन आबंटन में कुशलता बढ़ाने के लिए संविभाग में विविधता लाना आवश्यक है। नीति के दृष्टिकोण से विविध देशों में वित्तीय स्थिरता हेतु बढ़ती हुई चिंता के बीच, बैंकों के संविभाग में विविधता के उपाय बेहद महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। वित्तीय स्थिरता के अनुप्रयुक्त मानकों ने विभिन्न देशों में बैंकिंग क्षेत्र के संस्थागत स्वरूप, बाजार प्रतिस्पर्धा के आधार स्वरूप के मूल्यांकन और विश्लेषण हेतु प्रादेशिक और क्षेत्रीय ऋण अभिनियोजन और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के वैकल्पिक उपाय समेकित किए हैं। ऋण सुपुर्दगी प्रणाली की प्रतिस्पर्धी कुशलता जानने के लिए ऋण बाजार संकेंद्रण के उपाय उपयोग में लाए गए हैं।

प्रायोगिक आधार पर अनेक दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। किसी देश के बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा के विस्तार का विश्लेषण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, देशी निजी बैंक और विदेशी बैंकों जैसे विभिन्न बैंक समूहों की सहभागिता के आधार पर किया गया है। अनेक अध्ययनों ने ऋण बाजार संकेंद्रण के विश्लेषण के लिए बाजार संकेंद्रण का हरुचँन एंड हर्फिंडल इंडेक्स (एचएचआइ)[4] उपयोग में लाया है (बीओइ, तिमाही बुलेटिन, 2004)। विश्व बैंक द्वारा विश्व में विनियमन और पर्यवेक्षण पर डेटाबेस अध्ययन विभिन्न देशों के बैंकिंग क्षेत्र के संकेंद्रण पर उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराता है। उक्त अध्ययन से यह पता चलता है कि 121 देशों में 102 देश ऐसे हैं जिनके पांच बड़े बैंक हैं। जमाराशि में जिनका भाग पचास प्रतिशत से ज्यादा है। दूसरी ओर 129 देशों में से 112 देश ऐसे को जिनके पांच बड़े बैंकों के पास आस्तियों का 50 प्रतिशत से ज्यादा भाग था (सारणी क)। उक्त अध्ययन के अनुसार, भारत के पांच बड़े बैंकों जमाराशि और आस्तियों में हिस्सा क्रमशः 41 प्रतिशत और 44 प्रतिशत था। भारत की स्थिति ब्राजील, चीली, मेक्सिको और मलेशिया जैसे कुछ देशों से बेहतर थी।

सारणी क: जमाराशि और आस्तियों में पांच बड़े बैंकों के विश्व भाग में बैंक संकेंद्रण

(अनेक देशों के आधार पर वितरण)

श्रेणी निम्नवत से ज्यादा या उसके बराबर (प्रतिशत में)	जमाराशि	आस्तियां
	बैंकों की संख्या	
30	116	125
45	107	113
50	102	112
70	71	75
80	52	58
90	35	38

स्रोत : विश्व बैंक, द्वारा विनियमन तथा पर्यवेक्षण डेटा ेस 2003।

सारणी ख: पांच बड़े बैंकों का अंश

(कुल से प्रतिशत)

देश	जमाराशियां	आस्तियां
ब्राजील	63	54
चीली	62	61
फ्रांस	70	60
जर्मनी	21	20
भारत	**41**	**44**
जापान	46	46
मलेशिया	57	56
मेक्सिको	80	80
फिलिपिन्स	46	43
इंग्लैंड	24	23
अमरीका	29	30

स्रोत : विनियमन और पर्यवेक्षण पर विश्व बैंक आधारभूत आँकड़े 2003

भारतीय संदर्भ में, ऋण बाजार संकेंद्रण का प्रायोगिक विश्लेषण कुछ उपयोगी दृष्टिकोण सामने लाता है। बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी प्रकृति ने देशी निजी और विदेशी बैंकों की बढ़ती हुई सहभागिता के कारण महत्त्वपूर्ण सुधार देखा है। समग्र जमाराशि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अंश 1990 के 92 प्रतिशत से कम होकर 2004 में 78 प्रतिशत रह गया जबकि देशी निजी बैंकों का अंश 1990-91 के 4 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 15 प्रतिशत हो गया। बैंक ऋण के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अंश 1991-92 के 92 प्रतिशत से कम होकर 2003-04 में 74 प्रतिशत रह गया। बैंक ऋण में देशी निजी क्षेत्र के बैंकों का अंश 1991-92 के 3 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 19 प्रतिशत हो गया जबकि विदेशी बैंकों का अंश 1991-92 के 4 प्रतिशत से बढ़कर 2003-04 में 7 प्रतिशत हो गया। अधिक प्रतिस्पर्धा ने ग्राहकों को बैंकों में निधि रखने और साथ ही कम लागत पर उधार लेने के व्यापक विकल्प उपलब्ध कराए हैं।

ऋण के उद्योग-वार अभिनियोजन का प्रयोग करके किया गया एचएचआइ इंडेक्स का आकलन दर्शाता है कि 1991-92 के 1300 का दायरा 2003-04 में कम होकर 800 रह गया जिससे बैंक ऋण संविभाग विविधीकरण और ऋण बाजार संकेंद्रण में गिरावट का सुझाव मिलता है। मुख्यतः कृषि, लघु उद्योग, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, मध्यम और बड़े उद्योग और थोक व्यापार में ऋण के केंद्रीय अभिनियोजन पर आधारित एचएवआइइंडेक्स उपाय यह भी दर्शाते हैं कि कुछ वर्षों में ऋण संकेंद्रण कम हो गया है।

संदर्भ :

बैंक ऑफ इंग्लैंड (2004), 'बैंकिंग कंसन्ट्रेशन इन यू के', फिनशियल स्टैबिलिटी रिव्य, जून, आर्टिकल 7।

विनियमन और पर्यवेक्षण पर विश्व बैंक आधारभूत आंकड़े 2003।

[4] एचएफआइ इंडेक्स = Σएन $_{1=1}$ 2 एस$_2$, जहां एस समय-सीमा ठटीड के दौरान कुल बैंक ऋण में किसी उद्योग/कार्य/क्षेत्र के बैंक ऋण का अंश है। कुछ वर्षों में एचएफआई के उच्च मूल्य से यह स्पष्ट होता है कि गत वर्षों में एचएफआइ का वृद्धिशील संकेंद्रण और विपरीत कम मूल्य विविध क्षेत्रों को ऋण आबंटन में सुधार दर्शाता है।

3.30 हाल के वर्षों में, ऋण वृद्धि को गैर-कृषि गैर-औद्योगिक क्षेत्रों विशेषकर आवास, छोटे परिवहन परिचालकों तथा खुदरा ऋण से बढ़ावा मिला है। बैंकों से उपलब्ध ऋण के क्षेत्रीय अभिनियोजन संबंधी विस्तृत जानकारी से स्पष्ट होता है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान (अगस्त 2004 तक) ऋण प्रवाह का दो-तिहाई से अधिक भाग खुदरा, आवास और अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधारों के कारण है। उपलब्ध अधिक अद्यतम सूचना से औद्योगिक ऋण में पुनरूत्थान (सुधार) का संकेत मिलता है। उद्योगों में उल्लेखनीय वृद्धि पेट्रोलियम, बुनियादी सुविधा, विद्युत, विनिर्माण, धातु और धातु उत्पाद, भेषज और औषधियां, रत्न और आभूषण तथा मोटर वाहन में देखी गयी।

3.31 जबकि ऋण देने में विस्तार हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी कंपनी क्षेत्र के बॉण्ड/डिबेंचर/शेयर वाणिज्यिक पत्र (सीपी) आदि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश में 0.6 प्रतिशत की कमी की तुलना में 29 अक्तूबर 2004 तक 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऐसे निवेश में कमी के बावजूद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र को संसाधनों (निधियों) का कुल प्रवाह 29 अक्तूबर 2004 तक काफी अधिक 16.4 प्रतिशत (आइडीबीआइ रुपांतर को घटाकर 12.7 प्रतिशत) बढ़ा जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में वृद्धि 5.9 प्रतिशत हुई थी। संसाधनों के प्रवाह में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि भी 27.1 प्रतिशत (आइडीबीआइ के रुपांतरण प्रभाव को घटाकर 23.1 प्रतिशत) पर अधिक थी जबकि एक वर्ष पहले यह 13.8 प्रतिशत थी। वित्त संस्थाओं तथा म्युचुअल फंडों द्वारा जारी लिखतों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश में इस वर्ष 154 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। जबकि अक्तूबर 2003 में 7,570 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। पूंजी निर्गमों, वैश्विक निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) रसीदें (जीडीआर / अमरीकी डिपॉजिटरी रसीदे (एडीआर) तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार सहित वाणिज्यिक क्षेत्र को संसाधनों निधियों का कुल प्रवाह बढ़कर 29 अक्तूबर 2004 तक 1,65,809 करोड़ रुपए हो गया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 66,857 करोड़ रुपए था।

3.32 2004-05 के दौरान सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवेश (29 अक्तूबर 2004 तक) 28,955 करोड़ रुपए था (16,762 करोड़ रु. आइडीबीआइ रुपांतरण को घटाकर) जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 84,031 करोड़ रुपए की तुलना में कम था ऐसा अंशतः ऋण मांग में वृद्धि के कारण था। परिणामतः वाणिज्यिक बैंकों की एसएलआर प्रतिभूतियों की अधिक धारिता 2,59,083 करोड़ रुपए अथवा एनडीटीएल के 14.5 प्रतिशत तक कम कर दी गयी। इस कटौती के बावजूद, संपूर्ण रूप से बैंकिंग प्रणाली के लिए एनडीटीएल के 39.5 प्रतिशत प्रभावी एसएलआर निवेश 25 प्रतिशत का न्यूनतम सांविधिक अनुपात की तुलना में अधिक बना हुआ है। चूंकि 2004-05 के दौरान ऋण मांग काफी अधिक बने रहने की संभावना है, इसलिए सरकारी प्रतिभूतियों के लिए सरकार का बाज़ार उधारकर्ता कार्यक्रम के परिवेश में निहितार्थ है।

3.33 व्यापक आर्थिक और मौद्रिक समुच्चयों के मूल्यांकन पर 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा से संकेत मिलता है कि कुल जमाराशियों में वृद्धि 2,18,000 करोड़ रुपए होगी जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था तथा वाणिज्यिक पत्रों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनी क्षेत्र के बाण्डों/डिबेंचरों/शेयरों, आदि में निवेश सहित गैर-खाद्य बैंक ऋण में लगभग 19.0 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है, जो पहले अनुमानित 16.0-16.5 प्रतिशत से उच्चतर है, उच्च ऋण प्रसार को बैंकिंग क्षेत्र से सरकार के निम्नतर उधार के कारण मुद्रा आपूर्ति पर अनुचित दबाव डाले बिना समायोजित किया जा सकता है, सरकारी उधार वृहतर होने की स्थिति में एमएसएस (बाजार स्थिरीकरण योजना) का प्रसार ऐसे उधार को सहज बनाएगा।

प्राधिकृत व्यापारियों के रूप में बैंकों की भूमिका

3.34 2003-04 में विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय सहित प्राधिकृत व्यापारियों का कुल कारोबार 1.5 प्रतिशत कम हो गया। अंतर बैंक घटक में, क्रय-विक्रय दोनों ही परिचालन मजबूत भारतीय रुपये के कारण दबा हुआ रहा। वणिक घटक में आयात-निर्यात गतिविध्यिों के कारण क्रय परिचालनों में वृद्धि और विक्रय परिचालनों में कमी देखी गई (सारणी III.9)। वणिक से अंतर-बैंक का कारोबार अनुपात वर्ष के दौरान 2.9-3.9 प्रतिशत के दायरे में रहा जोकि अनुकूल बाजार स्थितियों का द्योतक है।

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग आंकड़े

3.35 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के आंकड़े महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इनसे किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का शेष विश्व से एकीकरण की जानकारी प्राप्त होती है। रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) द्वारा विकसित सूचना प्रणाली की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग आंकड़े (आइबीएस) संकलित करके उनका प्रसार करता आ रहा है। स्थानमूलक बैंकिंग आंकड़े (एलबीएस) और समेकित

सारणी III.9: प्राधिकृत व्यापारियों के विदेशी मुद्रा कारोबार का संयोजन

(राशि मिलि. अ.डा. में अनुपात प्रतिशत में)

वर्ष	वणिक		अंतर बैंक		कुल	
	क्रय	विक्रय	क्रय	विक्रय	क्रय	विक्रय
1	2	3	4	5	6	7
1997-98	97,937 (14.9)	1,11,989 (17.2)	5,58,019 (85.1)	5,38,103 (82.8)	6,55,956 (100.0)	6,50,091 (100.0)
1998-99	1,18,097 (17.9)	1,34,587 (20.1)	5,40,752 (82.1)	5,34,294 (79.9)	6,58,849 (100.0)	6,68,881 (100.0)
1999-2000	1,23,747 (21.0)	1,28,294 (21.6)	4,66,042 (79.0)	4,65,844 (78.4)	5,89,789 (100.0)	5,94,139 (100.0)
2000-01	1,33,214 (18.4)	1,48,018 (20.8)	5,90,638 (81.6)	5,62,379 (79.2)	7,23,852 (100.0)	7,10,397 (100.0)
2001-02	1,34,966 (18.2)	1,37,420 (18.4)	6,04,678 (81.8)	6,10,295 (81.6)	7,39,644 (100.0)	7,47,715 (100.0)
2002-03	1,65,544 (21.0)	1,63,664 (20.6)	6,24,151 (79.0)	6,31,380 (79.4)	7,89,695 (100.0)	7,95,044 (100.0)
2003-04	1,96,553 (24.6)	1,53,961 (20.2)	6,01,993 (75.4)	6,08,833 (79.8)	7,98,546 (100.0)	7,62,794 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े कुल कारोबार में अंश है।

बैंकिंग आंकड़े (सीबीएस) के तहत प्रस्तुत भारत के आईबीएस संबंधी आंकड़े बीआइएस को दिए जाते है जोकि उनके तिमाही प्रकाशनों में शामिल किए जाते हैं।

3.36 2003-04 के दौरान, बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय देयताएं 10 प्रतिशत बढ़ी जबकि 2002-03 में यह वृद्धि 17 प्रतिशत थी जोकि आनेवाली अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरइ) जमाराशि में बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा उधारों की बड़ी मात्रा से प्रेरित थी। विदेशी मुद्रा उधार में वर्ष के दौरान 82 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई (सारणी III.10)। 2002-03 में दर्ज अनिवासी बाह्य खाता में वृद्धि 2003-04 में भी जारी रही। विदेशी मुद्रा उधार में पर्याप्त वृद्धि उत्पादक प्रयोजनों से निवासियों की विदेशी मुद्रा अपेक्षाओं को सहज बनाने के लिए पूंजी खाता से संबंधित उदारीकरण के कई उपायों के कारण देखी गयी। विशेषकर बैंकों के विदेशी

सारणी III.10: बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय देयताएं - प्रकारानुसार वर्गीकृत

(करोड़ रुपये)

देयता का प्रकार	बकाया राशि (मार्चांत)		
	2002	2003	2004
1	2	3	4
1. जमा राशियां और ऋण	1,20,604	1,45,930	1,78,994
जिनमें से:			
विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [एफसीएनआर(बी)]	39,636	43,989	45,386
योजना विदेशी मुद्रा उधार*	5,514	18,411	33,598
अनिवासी विदेशी रुपया (एनआरइ)	33,233	53,124	75,938
खाता अनिवासी गैर-प्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर) रुपया जमा राशियां	27,181	15,207	7,335
2. प्रतिभूति बांडों (आइएमडी/आर आइबी सहित) के अपने निर्गम	43,582	44,087	27,720
3. अन्य देयताएं	7,150	10,475	14,017
जिनमें से:			
एडीआर/जीडीआर	1,862	3,833	6,396
अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों के सामान्य शेयर	547	556	1,379
भारत स्थित विदेशी बैंकों की पूंजी/विप्रेषणीय लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतर्राष्ट्रीय देयताएं	4,741	6,086	6,242
कुल अंतर्राष्ट्रीय देयताएं	**1,71,336**	**2,00,493**	**2,20,730**

* भारत में और विदेश से अंतर बैंक उधार,बैंकों के विदेशी वाणिज्यिक उधार।